

अपील सूचना अधिकार संख्या 103/2020 (GCMS 2020/00174) रोबिन अग्रवाल निवासी 2 डी 35 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, वनाम प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर



22.06.2022


पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रोबिन अग्रवाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2020 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. कार्यालय अति. जिला कलक्टर (नगर), श्रीगंगानगर में पदस्थापित लिपिक श्रीमती कोमल जैन की सेवा पुस्तिका,
2. माह जुलाई, 2018 से माह दिसम्बर, 2019 की अवधि में आहरित चिकित्सा पुर्नभरण बिल,
3. माह जुलाई, 2018 की श्रीमती कोमल जैन का वेतन प्रमाण पत्र।

अति. जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ1(23)()स्था./2019/8218 दिनांक 19.10.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :




जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आरटीआई प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2020 द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को कार्यालय पत्रांक सम 6467 दिनांक 06.08.2020 द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित सूचना की चित्र प्रति सलग्न प्रस्तुत है।

अतः अपील जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी को उनके द्वारा प्रेषित आरटीआई प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2020 द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय पत्रांक सम 6467 दिनांक 06.08.2020 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। कृपया अपील खारिज करने का श्रम करें।

अति. जिला कलक्टर(प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी (स्थापना शाखा)
श्रीगंगानगर

चूंकि अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक 6467 दिनांक 06.08.2020 से सूचित किया जा चुका है साथ ही अपीलार्थी की द्वारा वांछित सूचना कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का मामला है जो कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी है जिसमें किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक हित नहीं है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना देय नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) निम्नानुसार अवलोकनीय है


जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(ज) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीयलोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का वह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।

उक्त के सम्बन्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 22/2009 अनवानी केनरा बैंक बनाम सी.एस. श्याम में दिनांक 31.08.2017 के पैरा संख्या 12 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

We are in agreement with the CIC and the courts below that the details called for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respondent, show-cause notices and orders of censure/punishment, etc. are qualified to be personal information as defined in clause (j) of Section 8(1) of the RTI Act. The performance of an employee/officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual. Of course, in a given case, if the Central Public Information Officer or the State Public Information-Officer or the appellate authority is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, appropriate orders could be passed but the petitioner cannot claim those details as a matter of right.

—4— अपील सूचना अधिकार संख्या 103/2020

चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी है जिसमें किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक हित नहीं है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(अ) के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना देय नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जानी उचित होगी।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती हैं। आदेश की प्रति अति. जिला (प्रशासन) एवं प्रीमरी अधिकारी (स्थापना शाखा), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुकमणि रिथार सिन्हा)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर